भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

COMMUNIST PARTY OF INDIA (MAOIST)

ओड़िशा राज्य कमेटी

ODISHA STATE COMMITTEE

प्रेस स्टेटमेंट **दिनांक : 5 अगस्त 2014**

माओवादी जनयुध्द के ओड़िशा-छत्तीसगढ़ बार्डर में बढ़ते कदम...
आईये जनयुध्द को हर तरह की मदद देते हुए जनता के पक्ष में खड़े हों!

21 सितंबर 2014 से महीने भर माओवादी पार्टी की दसवीं बरसगांठ को जोरशोर के साथ मनाओ!

बरस 2004, दिनांक 21 सितंबर, भारत की क्रांति में एक ऐतिहासिक दिन. इस बरस उस दिन को पूरे दस साल हो रहे हैं. एक ऐसा दिन जिसने देश की उत्पीड़ित क्रांतिकारी जनता, क्रांतिकारी ताकतों, प्रगतिशील, जनवाद पसंद बुध्दिजीवियों, भारतीय जनता के सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन कर रही अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी माओवादी ताकतों के दिलों को खुशियों से भर दिया था. और एक ऐसा दिन जिसने भारत के दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों, बड़े-बड़े सामंतों, और उनके मालिक विभिन्न साम्राज्यवादी देशों व खासकर अमेरीकी साम्राज्यवाद के दिलों में हड़कंप मचा दिया था. एक ऐसा दिन जिस दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री ने कहा - माओवादी देश की आंतरीक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है! वह दिन था दोस्तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (पीपूल्सवार) और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (एमसीसीआई) के विलय का दिन! अलग-अलग धाराओं के रुप में आंदोलन चला रही ताकतों की एकजुटता का दिन!

दरअसल खतरा देश की आंतरीक सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि माओवादी पार्टी के नेतृत्व में चल रहा जनयुध्द दलाल बड़े पूंजीपतियों, विदेशी कंपनियों और जमींदारों द्वारा जारी लूट को था. देश के शोसक–शासकों को पता था कि दो बड़ी माओवादी पार्टियों के विलय से माओवादी आंदोलन न केवल अखिल भारतीय स्वरुप का आंदोलन बन जायेगा बल्कि उसकी सैनिक ताकत भी बढ़ जायेगी. यही हुआ! माओवादी पार्टी ने अपनी पीएलजीए की मदद से भारतीय क्रांति को ऐतिहासिक रुप से आगे बढ़ाया है. न केवल सैनिक रुप से बल्कि राजनैतिक रुप से भी माओवादी पार्टी भारत की शोषित–उत्पीड़ित जनता के लिए एक विकल्प बनकर उभरी है. दुनिया भर की माओवादी, क्रांतिकारी ताकते, विश्व समाजवादी क्रांति में भाकपा (माओवादी) के बढ़ते योगदान की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है. माओवादी पार्टी खासतौर से देश के सबसे उत्पीड़ित, पिछड़े, सरकारों द्वारा सदियों से उपेक्षित आदिवासी इलाकों में काफी हद तक लूटेरी, विदेशी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट के सामने एक चुनौती पेश कर रही है, एक हद तक उनकी लूट पर अंकुश लगा पाई है. वन विभाग द्वारा किये जाने वाले शोषण–उत्पीड़न, लूट, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़, बेगारी आदि पर रोक लगा पाई है, उसने आदिवासी जनता का सम्मान और इज्जत के साथ जीना सीखाया है, अपने अधिकारों के लिए सशस्त्र होकर लड़ने के लिए प्रेरित किया है, आज देश के आदिवासी अपने जल-जंगल व जमीन के लिए जी-जान से लड़ रहे हैं. आज वह नारा लगा रहे हैं कि जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे!

पार्टी विलय के एक साल बाद यानि 2005 में यूएपीए सरकार ने एक तरह से देश की जनता के खिलाफ अघोषित युध्द छेड़ दिया. माओवादी पार्टी के निर्मूलन के लिए केंद्रीय स्तर पर अभूतपूर्व रुप से प्रयास तेज हो गए. 5 जून 2005 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला ग्राम कुटरु से सलवा जुडूम की शुरुआत हुई. सलवा जूडुम फासीवादी अभियान ने 600 से ज्यादा गांवों को जला कर राख कर दिया, सैकड़ों महिलाओं के साथ सरकारी सशस्त्र बलों, विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) ने सामूहिक बलात्कार किये, फसलों को तबाह कर दिया, और हजार से ज्यादा लोगों को मार डाला. लेकिन बस्तर की आदिवासी जनता ने, हमारी पार्टी के नेतृत्व में, और प्रगतिशील, जनवादी बुध्दिजीवियों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के समर्थन से इस फासीवादी दमन अभियान को नाकों चने चबवाए. विश्वस्तर पर माओवादी जनयुध्द को समर्थन प्राप्त हुआ. पीएलजीए ने लड़ते हुए युध्द को सीखा और दुश्मन के फासीवादी बलों को करारे सबक सिखाए. हजारों की संख्या में जन मिलिशिया का गठन हुआ, सैकड़ों मिलिशिया सदस्य पीएलजीए में भर्ती हुए और देश की मुक्ति की लड़ाई में कूद पड़े. दंडकारण्य में इस क्रूर दमन का सामना करते हुए जनता ने ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक अपनी जनताना सरकारों का निर्माण किया. आज जोन स्तरीय जनताना सरकार बनाने की तरफ दंडकारण्य की जनता आगे बढ़ रही है.

क्रांतिकारी जन कमेटी (जनताना सरकार) अपने कृषि विभाग के जरिये हजारों एकड़ जमीन को खेती योग्य बनाने में कामयाब हुई है. लाखों महिला-पुरुषों, बच्चों, बुर्जुगों और जनमिलिशिया, पीएलजीए की मदद से यह संभव हो सका है. उसने अपने शिक्षा विभाग के तहत स्कूलों का संचालन शुरु किया है जिसमें सैकड़ों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. जनताना सरकार के

अपने स्वास्थ्य विभाग है जिसके जन डॉक्टर हजारों जनता तक निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहे हैं. जनताना सरकारों के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन आगे बढ़ रहा है. न्यायीक विभाग बिना देरी किये, जनता से ही न्यायधिश चुन कर फैसले सुना रहा है, बिना देरी व बिना खर्च जनवादी फैसले जनता को मिल रहे हैं. इन जनताना सरकारों के संचालन में उनकी सुरक्षा करते हुए जन मिलिशिया अहम योगदान निभा रहा है. जनताना सरकारों का सुरक्षा विभाग इसका संचालन करता है.

सलवा जुडूम की करारी हार के बाद तिलमिलाए शोषक-शासक वर्गों ने कोबरा फोर्स का गठन करके और भी क्रूर और फासीवादी ऑपरेशन ग्रीनहंट अभियान की शुरुआत की. यह क्रूर अभियान आज भी जारी है. लेकिन हमारी पीएलजीए और क्रांतिकारी जनता इसका डटकर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रही है.

इस दौरान जनता का दमन करने वाले फासीवादी बलों का पीएलजीए ने जनता की मदद से बहादुरी पूर्ण मुकाबला किया और उस पर कई ऐतिहासिक हमले किये. दंडकारण्य में रानीबोदली, उरपलमेट्टा, लाहेरी, टव्वेटोला, मदनवेड़ा, कोंगेरा, ताड़मेटला, मुकरम, ओड़िशा में नयागढ़, बालिमेला, कलिमेला, बिहार-झारखंड में लखिसराय, सारंडा, गिरडिह, पश्चिम बंगाल में सिलदा रेड आदि प्रमुख है. सैकड़ों दुश्मनों का सफाया कर सैकड़ो हथियार पीएलजीए ने जब्त किये हैं. वहीं जहानबाद, लखिसराय, दंतेवाड़ा आदि जेल ब्रेक कर कई वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं व सैकड़ो निर्दोष जनता को छुड़वाने में हमारी पार्टी कामयाब हुई है.

इन दस सालों में हमारी पार्टी ने कई ऐतिहासिक जन आंदोलनों को खड़ा किया है, उनमें भागीदारी की है. जनता के हर जायज आंदोलन के साथ हमारी पार्टी खड़ी रही है.

1967 में पश्चिम बंगाल ने नक्सलबाड़ी विद्रोह खड़ा कर देश की क्रांति को नई राह दिखाई थी. एक बार फिर माओवादी पार्टी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की जनता विस्थापन के खिलाफ उठ खड़ी हुई और पूरे भारत के विस्थापन विरोधी आंदोलनों को राह दिखाई. पश्चिम बंगाल के सिंगुर में टाटा कंपनी को भागना पड़ा, नंदीग्राम से इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा और लालगढ़ इलाके से बड़े व दलाल पूंजीपति जिंदाल को उलटे पांव लौटना पड़ा. इतना ही नहीं 35 सालों से जड़ जमा कर बैठे सामाजिक फासीवादी नकली मार्क्सवादियों के शासन को भी जनता ने उखाड़ फैंका. अमर शहीद, भारतीय क्रांति के प्यारे नेता कामरेड किशनजी की रहनुमाई में लालगढ़ की जनता ने नक्सलबाड़ी विद्रोह की याद ताजा कर दी. इस ऐतिहासिक विद्रोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनता का समर्थन प्राप्त हुआ. केंद्र व राज्य सरकारों की नींद हराम कर दी गयी.

ओड़िशा में पीछले दस सालों में माओवादी आंदोलन बालको, नालको, वेदांता, पोस्को, टाटा, मित्तल, जिंदल आदि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए लाल भूत बनकर खड़ा हुआ है. खदान माफियाओं के लिए सिरदर्द बन गया है. माओवादी पार्टी के समर्थन व नेतृत्व में ओड़िशा की जनता खासकर आदिवासी जनता विस्थापन व शोषण के खिलाफ उठ खड़ी हुई है. खासतौर से बॉक्साईट के अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं से जनता टक्कर ले रही है. कहा जाता है कि बॉक्साईट की खदान खोलने वाली कंपनियों दुनिया के किसी भी कौने में नहीं हारी, शाम-दाम-दंड-भेद से खदाने खोल लेती हैं, चाहे उसके लिए देशों का तख्तापल्ट क्यों न करवाना पड़े लेकिन ओड़िशा की जनता ने उनकी लूट को चैलेंज किया है. नियमगिरी, गंदमर्दान पहाड़ों को अपना देवता मानकर जनता उनकी रक्षा के लिए जीवन मरण का संघर्ष कर रही है. जनता के संघर्ष की बदौलत नियमगिरी में तो खुद सुर्पीम कोर्ट में फैसला सुनाना पड़ा की जनता से अनुमति लिए बिना कोई खदान कार्रवाई शुरु नहीं होगी. यह बात अलग है कि चुनावों के समय फिर सरकार ने पिछले दरवाजे से खनन की अनुमति दे दी. कलिंगनगर में टाटा, जगतसिंगपुर में पोस्को, लांजीगढ़-नियमगिरी में वेदांता के खिलाफ जनता निर्णायक लड़ाई लड़ रही है.

नारायणपटना के आदिवासियों की लड़ाई ने फिर एक बार जमीन जोतने वाले व सामंती शोषण को भारतीय राजनीति के पटल पर रखा. संशोधनवादी पार्टियों के अवसरवादी नेतृत्व से मुक्ति पाकर जनता ने साहूकारों, जमींदारों, सूदखोरों व शराब माफियाओं के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन छेड़ा और विजय हासिल की.

दो महाधाराओं के विलय के बाद 2007 में संपन्न ही एकता कांग्रेस-नौवीं कांग्रेस के दिशा-निर्देशों के अनुसार माओवादी पार्टी ने अपने आंदोलन का विस्तार किया. देश के दो प्रधान जोन दंडकारण्य और बिहार-झारखंड के बीच के इलाके यानि ओड़िशा को इस विस्तार के लिए महत्वपूर्ण माना गया. आज हमारी ओड़िशा राज्य कमेटी इस महत्वर्पूण कार्यभार को लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के नगरी-सिहावा व रायपुर जिला के गरियाबंद, मैनपुर ब्लॉक से इस विस्तार की शुरुआत हुई. अब वह इलाका गरियाबंद जिला में आता है. सबसे पहले मैनपुर डिवीजन का गठन हुआ. डीकेएसजेडसी के नेतृत्व में यहां आंदोलन के विस्तार की शुरुआत हुई थी. 2007 में एक प्लाटुन की संख्या हमारी पार्टी धमतरी जिला के नगरी-सिहावा, सीतानदी एरिया में कदम रखी. उसके बाद रायपुर जिला के गरियाबंद, मैनपुर, उदंती एरिया में आगे बढ़ी. जनता ने दिल खोल कर स्वागत किया जैसे वह बरसों से हमारे आंदोलन का इंतजार कर रही हो. जहां भी दस्ता जाता लोग स्वागत के लिए खड़े होते, लाल सलाम करते और अपनी समस्याएं सामने रखते. जनता जंगल-पहाड़ों में पार्टी को देखने के लिए आती थी. क्योंकि यह इलाका सितानदी-उदंती वन अभ्यारण्य में आता था. वहीं ओड़िशा के नुआपाड़ा जिला का सोनाबेड़ा इलाका भी एक वन अभ्यारण्य है. ये दोनों सटे हुए हैं. इस प्रकार सीतानदी, उदंती, सोनाबेड़ा की आदिवासी जनता सालों से इन वन अभ्यारण्यों के खिलाफ लड़ रही थी. वन विभाग इनका मनमाना शोषण करता था. वनों से लकड़ी लाना, तेंदुपत्ता तोड़ना, गाय-भैंस चराना,

वनोपजों का संग्रहण करना आदि सब मना था. कोई खेती के लिए जमीन नहीं काट सकता था. अगर ऐसा कोई करता तो वन विभाग केस लगा कर जेल भेज देता था. जनता कोर्ट की तारीख पर तारीख के चक्कर में पड़ कर कंगाल बन जाती थी. मजबूरीवश वन विभाग के गार्ड से लेकर डीएफओ तक को रिश्वत देनी पड़ती थी. जनता इन सब से बहुत तरस्त थी. जैसे ही पार्टी ने कदम रखे फारेस्ट डिर्पाटमेंट अपनी वर्दियों को लगाना छोड़ दिया और अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया. बरसों से संघर्ष कर रहे और लूट रहे लोगों को बहुत चैन मिला. उनका सबसे बड़ा दुख दूर हो गया. इस प्रकार पार्टी को जनता 'भगवान' की तरह देखती व दूर दूर से अपने गांव में आने का न्यौता भेजती थी. आज यह आंदोलन ओड़िशा और छत्तीसगढ़ कई जिलों में फैल गया है.

- ☞ वन विभाग के भागने से हजारों भूमिहीन किसानों, बड़ी संख्या में गरीब किसानों को भी जमीने मिलीं. लगभग सभी गांवों से भूमिहीनता की समस्या तो दूर हुई है. इसी तरह लघु वनौपजों के संग्रहण की अनुमति देने, तेंदुपत्ता तोड़ाई की मजदूरी बढ़वाने के लिए भी हजारों जनता जन आंदोलनों में गोलबंद हुई. तेंदुपत्ता तुड़वाई की मजदूरी बढ़वाने के लिए 2012 में नुआपड़ा जिला मुख्यालय पर 3000 के आसपास लोगों ने रैली की. वनोपज के दाम बढ़वाने के लिए तुरेकेला में 5000 से ज्यादा लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. जनता ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बंद का आव्हान दिया, जो सफल रहा. भावसिल, कटिनपानी आदि गांवों में साहूकारों, बड़े व्यापारियों व जमींदारों की जमीनों को जनता ने जब्त किया.
- ☞ पार्टी का प्रभाव दूर-दूर तक फैला. इसको देख कर 2010 में मैनपुर डिवीजन से फिर आंदोलन विस्तार हुआ. पार्टी के नेतृत्व में ओड़िशा बरगढ़, बलांगिर और छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिलों तक विस्तार किया. इस विस्तार के दौरान हमारे कई प्रिय कामरेड शहीद हुए. लेकिन आज उनकी बदौलत हमारी पार्टी बरगढ़-बलिंगर-महासमुंद डिवीजनल कमेटी का गठन कर जनता को क्रातिंकारी आंदोलन में गोलबंद कर पा रही है. उस इलाके में जमींदारों के खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई है. सामंती शोषण को चुनौती दे रही है. सूदखोरों द्वारा जब्त की गयी जमीन व गिरवी रखवाई जमीन को जनता ने संघर्ष फिर से वापिस अपने हाथों में लिया है. आज फिर वह किसान अपने खेतों को जोत रहे हैं.
- ☞ वन अभ्यारण्यों के खिलाफ जनता लगातार संघर्षरत है. अभ्यारण्य के गांवों में न तो पीने के लिए पानी की सुविधा है, न खेती के लिए अनुमति और सिंचाई की सुविधा है. बिजली के कनेक्शसन नहीं दिये जाते, लघु वनोपज के संग्रहण पर पूरी तरह से प्रतिबंद है. जमीनों का पट्टा भी नहीं दिया जाता. इन तमाम समस्याओं को लेकर सीतानदी और उदंती की जनता के संघर्ष को दबाने के लिए कई आंदोलनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. इसके खिलाफ 2009 में ग्रामीणों को रिहा करने की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हजारों जनता ने विरोध प्रदर्शन किया. मैनपुर पुलिस थाना के सामने हजारों महिला व पुरुषों ने चक्काजाम किया.
- ☞ गंदमर्धान पहाड़ बलांगिर-बरगढ़ जिलों में है, यहां ओड़िशा में बॉक्साइट के दूसरे सबसे बड़े भंडार हैं. एल्युमिनियम कंपनी बालको यहां पर अपनी गिध्द दृष्टि जमाये हुए है. लगभग तीस सालों से जनता लगातार इन खदानों के विरोध में आंदोलनरत है और अपने खनिज भंडारों की रक्षा कर रही है. गंदमर्धन बॉक्साइड खदन विरोधी आन्दोलन का हमारी पार्टी समर्थन करती है। माओवादी पार्टी के यहां विस्तार होने के बाद जनता में नया जोश आया है.
- ☞ बलांगिर जिला पुजारपली में बांध का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 27 गांव डूब जाने का खतरा है. इस बांध के विरोध में 2011 से आंदोलन जारी है. विस्थापन के खिलाफ जनता अपनी आवाज ऊंचा उठाये हुए है. जिस कारण 27 गांवों विस्थापन के खतरे से बच गए हैं.
- ☞ गंदमर्धान से निकलने वाली नदियों पर कई बांध प्रस्तावित हैं. इन्हीं में से एक है लोयार सुकतेल बांध. इसकारण से दर्जनों गांवों विस्थापित हो जायेंगे और हजारों एकड़ कृषि व वनभूमि का नाश होगा अलग. इसलिए जनता लोयर सुकतेल बांध निर्माण के खिलाफ भी आंदोलन का झंडा उठाये हुए है.
- ☞ क्रांतिकारी आंदोलन विस्तार से पहले ओड़िशा के नुआपाड़ा व छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिलों के ज्यादातर इलाकों में गांजा माफिया, वन विभाग व पुलिस की मिलीभगत से गांजा की खेती होती थी. भुखमरी व गरीबी का शिकार आदिवासी जनता उनके चंगुल में फंसी हुई थी. लेकिन जब क्रांतिकारी आंदोलन ने अपनी आमद दर्ज करवाई तो वन विभाग के साथ-साथ गांजा तस्करों को भी यहां से भागना पड़ा. जनता ने भी अपनी खेती-बाड़ी पर ध्यान देकर अपने विकास की शुरुआत की.
- ☞ इलाके में आदिम जनजाति कमार का निवास स्थान है. कमार जाति बेहद पिछड़ी है. वह खेती बाड़ी करना नहीं जानती. जंगल से बांस लाकर उससे सूप, टोकरी, डलिया आदि बनाकर अपना जीवनयापन करती है. उसका मुख्य पेशा हस्तशिल्प ही है. लेकिन जंगल से बांस लाना कमार जनता के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी करता था. सेंचूरी के नाम से वन विभाग मनमानी लूट करता, उनके दारु-मुर्गों की मांग करता और उनको जेल भेजने की धमकियां देता था. जनता वन विभाग के अमले से बहुत परेशान थी. लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार के बाद कमार जनता से वन विभाग का खोफ खत्म हुआ है और उसने हस्तशिल्प के साथ-साथ खेती बाड़ी करना

भी शुरु किया है. उनको पिछड़े पन की दलदल में धकलने का काम सरकार व वन विभाग का ही है जो उनको न तो बांस भरपुर काटने देता था न ही घर व खेती करने के लिए जमीन ही काटने देता था. अब क्रांतिकारी आंदोलन की ताकत के बल पर वह अपनी किस्मत खुद लिख रहा है. क्रांतिकारी जन संगठन लगातर उसे खेती-बाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनको बीज, खाद, हल-बैल, इंजन आदि हर प्रकार की मदद दे रहे हैं.

- ☞ इस इलाके में जंगल भरपुर होने के चलते और मैदानी इलाकों में फसलों से भरे खेत होने के चलते भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़ आदि चराने वाले लोग पहाड़ के ऊपर डेरा डालते हैं. लेकिन वन विभाग इनको भी अपनी लूट का शिकार बनाता रहा है. भैंस वालों का दूध, घी, भेड़-बकरी वालों से बकरों की मांग करके उन्हें लूटता था. मनमर्जी से बकरियां उठा कर ले जाता था. जो उसे नहीं देते उन्हें केस लगाने की धमकियां दी जाती थीं. लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन के बल पर आज बेखोफ होकर चरवाहे अपना जीवन यापन चला रहे हैं.
- ☞ कहते हैं बिना रोए तो मां भी दूध नहीं देती. मतलब बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता. कमार, भूंजिया, कुव्वी, गोंड जैसी जनजातियों को सरकार दशकों उपेक्षित रखती आई है. उनके प्रति सरकार ने सौतेला रवैया अपनया है. उनकी अनदेखी की है लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन ने आज आदिवासी जनता के मुद्दों को न केवल भारतीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का मुद्दा बना दिया है. आज सरकार को उनके 'क्लयाण' के लिए 'योजनाओं' की घोषणा करनी पड़ रही है. झूठे सुधारों को लागू करना पड़ रहा है. तहसिलदार तक जिन इलाकों में झांक कर नहीं देखता था वहां केंद्रीय केबिनेट मंत्रियों को आना पड़ रहा है. जनता इसे 'चमत्कार' कहती है.

उसको एहसास हो रहा है कि हमारी ताकत से दिल्ली दहल रही है, दिल्ली तक सरकार अब हमें देख रही है! हालांकि यह सब क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए ऑपरेशन ग्रीनहंट का ही हिस्सा है लेकिन कुछ भी हो - जनता का अपनी ताकत पर भरोषा बढ़ता जा रहा है.

हमारी पार्टी के नेतृत्व में जनता के जारी संघर्ष से घबरा उठी विदेशी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और जमींदारों की लूट को जारी रखने के लिए माओवादी आंदोलन को कुचलने के लिए ऑपरेशन ग्रीनहंट चलाया जा रहा है. हम कहते हैं हमारा आंदोलन जनता का जायज आंदोलन है. यह एक न्यायीक युध्द है. जबकि लूटेरे शासक वर्ग जो जनता पर लाखों सशस्त्र बलों को उतार रहे हैं, हवाई हमलों की तैयारी कर रहे हैं वह पूंजीपति व जमींदारों के फायदे के लिए किया जाने वाला नजायज व अन्यायपूर्ण युध्द है. यह युध्द उन तमाम लोगों के खिलाफ है जो विस्थापन, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, और अपने जल-जंगल-जमीन के लिए लड़ रहे हैं. क्योंकि सरकार को डर यह सारे लोग आने वाले समय में माओवादी ही बनेंगे!

दोस्तो युध्द जारी है, टाई और लंगोटियों के बीच, झोपड़ी और कोठियों के बीच, आपको तय करना है आप किसके पक्ष में हैं, आदमखोरों की ओर हो या आदमी की ओर हो! हमारा लक्ष्य सीधा है, देश को आजाद करवाने के लिए, सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान के लिए, हर हाथ को काम हर व्यक्ति को सम्मान के लिए, आदिवासी, दलित जनता के विकास के लिए, महिला-पुरुषों की समानता के लिए बड़े दलाल पूंजीपतियों, जमींदारों, साम्राज्यवादियों को उखाड़ फैंकना है. इसके लिए मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, कर्मचारी,छात्र, अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय पूंजीपति सब हमारे दोस्त हैं. आईये मिलकर एक नवजनवादी भारत के सपने को साकार करें. आईये माओवादी जनयुध्द को हर तरह की मदद देते हुए जनता के पक्ष में खड़े हों!

इंकलाबी अभिवादन के साथ

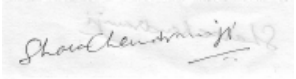

शशतचंद्र मांझी
प्रवक्ता
ओड़िशा राज्य कमेटी
भाकपा (माओवादी)